ब्लाइंड खिलाड़ियों को 25 लाख देगी सरकार

तीन महिला खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में भेंट की

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 13 दिसंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शनिवार को ब्लाइंड विमेंस टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल जीतने वाली भारतीय टीम में शामिल प्रदेश की तीन महिला खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में भेंट की.

खिलाड़ियों में सुश्री सुनीता सराठे, सुश्री सुषमा पटेल और सुश्री दुर्गा येवले शामिल हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए तीनों खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप 25-25 लाख रूपए प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से 10-10 लाख रूपए नगद और 15-15 लाख रूपए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में होंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तीनों खिलाड़ियों और तीनों कोच का ट्राफी और अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मान किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश का नाम रौशन करने वाली तीनों खिलाड़ियों की आगामी पढ़ाई और कोचिंग आदि की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महिला खिलाड़ियों के कोच सोनु गोलकर, ओमप्रकाश पाल और दीपक पाहड़े को एक-एक लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की.

नेपाल को हराकर दर्ज की ऐतिहासिक जीत

उल्लेखनीय है कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने महिला टी-20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2025 के फाइनल मैच में नेपाल को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम में मप्र की उपरोक्त तीन प्रतिभावान खिलाड़ी शामिल थीं. इनमें ऑलराउंडर केटेगरी में खेलने वाली सुश्री सुनीता सराठे नर्मदापुरम, सुश्री सुषमा पटेल दमोह और बेट्समेन तथा विकेटकीपर के रूप में खेलने वाली सुश्री दुर्गा येवले बैतूल से हैं.

मंत्रालय के गलियारे से

कन्हैया लोधी

अब केवल रिटायरमेंट की चाहत

मप्र के टॉप ब्यूराक्रेट्स में से एक को अब केवल रिटायरमेंट की चाहत है. साहब लंबा प्रशासनिक अनुभव रखते हैं, उनता बड़ा रूतबा भी है. सरकार में बड़ी-बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन अब रिटायरमेंट की दहलीज पर हैं. वैसे अभी के हालातों में यदि परिस्थितियां बनीं, तो वे सेवावृद्धि के हकदार भी हो सकते हैं, यदि सेवावृद्धि न भी मिले तो रिटायरमेंट के बाद भी सरकार के किसी बड़े संस्थान में बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, लेकिन अब साहब थकने लगे हैं. उनके मुताबिक जितनी बड़ी जिम्मेदारी, उतना ज्यादा काम, ऐसे में न शरीर को आराम और न परिवार का पूरा ध्यान. अब समय है कि रिटायरमेंट के बाद पूरा समय परिवार को दें. अब देखना ये है कि साहब अपनी मंशा के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद आराम करते हैं या फिर सरकार उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी से नवाजती है.

क्लास जिसे चारदीवारों तक सीमित कर दी गई

पिछले दिनों चुनाव सुधार को लेकर दिल्ली से क्लास लगी, इस क्लास में सत्ताधारी दल के कई विधायक शामिल हुए. इस क्लास में समझाया गया कि चुनाव सुधार के क्या-क्या फायदे हैं. माननीय ने बेहद अनुशासित तरीके से इस क्लास को अटेंड किया, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये कि इस क्लास को लेकर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई. बस तब से ही चर्चा है कि आखिर इसमें और ऐसी क्या बातें कहीं गई, जो कि घर के चारदीवारों तक ही सीमित कर दी गई.

मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है

पिछले दिनों जंगल से जुड़े एक बड़े मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बड़ी गर्मा-गर्मी रही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस क्षेत्र से इस मुद्दे का सरोकार था, वहां के किसी माननीय इतना मुखर नहीं हुए, जितना कि क्षेत्र से दूर-दराज के नेता रहे. इस मामले में उनकी सक्रियता के मायने निकाले जा रहे हैं. दरअसल जिस मुद्दे को विवादित बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे बड़े कार्पोरेट जुड़े हुए हैं. लिहाजा लोग इसे प्रेशर पॉलिटिक्स से भी जोड़ रहे हैं. इधर प्रोजेक्ट से जिस क्षेत्र को फायदा होना है, वहां से जुड़े माननीय भी ये कहते पाये गये कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है.

अटकलों का दौर

प्रदेश के कद्दावर नेता को क्या केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. ये सवाल पिछले कुछ माह से तो खुले आसमां में तैर ही रहा है, अब तो इस सवाल ने बेहद रफ्तार भी पकड़ ली है. जब तक आधिकारिक नियुक्ति नहीं हो जाती, ये सवाल लगातार बना रहेगा. अब देखना ये है कि ये सवाल कितना सटीक बैठता है. बहरहाल जो भी हो, वजनदारी बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं.

सिंहस्थ के लिए 25 हजार करोड़ की परियोजनाएं

उज्जैन, 13 दिसंबर. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के दो वर्षों के नेतृत्व में प्राचीन नगरी उज्जैन में आगामी 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को लेकर यहां चल रहे 25 हजार करोड रुपए से अधिक की परियोजनाएं के विकास कार्य चल रहे हैं.

आधिकारिक जानकारी में बताया कि इस नगरी में प्रत्येक 12 वर्ष में पुण्य सलिला शिप्रा के तट पर सिंहस्थ महापर्व का आयोजन होता है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़े धार्मिक समागमों में से एक है. सिंहस्थ नाम, ज्योतिषीय गणना पर आधारित है. जब बृहस्पति (गुरु) ग्रह सिंह राशि पर और सूर्य मेष राशि पर विराजमान होते हैं, तब यहां सिंहस्थ .कुंभ. का आयोजन होता है. राजा विक्रमादित्य की राजधानी रही यह भूमि, शून्य और पंचांग की गणना का केंद्र थी.

महाकवि कालिदास ने यहीं मेघदूत की रचना की, और महर्षि सांदीपनि के आश्रम में भगवान श्रीकृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की. उज्जैन केवल धर्म का केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय खगोल विज्ञान और गणित का भी ध्रुव केंद्र रहा है. मुख्यमंत्री का मुख्य उद्देश्य है कि सिंहस्थ 2028 तक महाकाल परिसर को ऐसा बनाना, जहाँ एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को विश्व-स्तरीय सुविधाएं मिल सकें. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ यादव ने पिछले दो वर्षों के दौरान विश्व प्रसिद्ध भगवान महाकालेश्वर मंदिर की नगरी को विश्वस्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में बनाने के लिए युद्धस्तर पर अधोसंरचना विकास कार्य किए जा रहे हैं.

> डॉ. यादव के नेतृत्व में पिछले दो वर्षों से उज्जैन के विकास को एक नई और महत्वाकांक्षी दिशा मिली है. चूंकि डॉ. यादव स्वयं उज्जैन से हैं, इसलिए इस नगरी के विकास की संकल्पना उनके लिए केवल राजनीतिक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है. उनका कार्यकाल उज्जैन को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की उपलब्धियों पर केंद्रित रहा है.

विकास के हर क्षेत्र में सरकार कर रही है कार्य : शुक्ल

भोपाल/सागर, 13 दिसंबर. मध्यप्रदेश सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार विकास के हर क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है और किसी भी क्षेत्र को उपेक्षित नहीं छोड़ा गया है.

वे शनिवार को सागर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे. उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को सिकल सेल एनीमिया और टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं. राज्य में निरोगी काया अभियान, एयर एम्बुलेंस सेवा, जिला अस्पतालों में शव वाहन सुविधा, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, हर घर नल से जल, सांदीपनि विद्यालय, पीएम श्री कॉलेज जैसी योजनाओं के माध्यम से आमजन को सीधा लाभ मिल रहा है.

भोपाल समेत कई शहरों में शीतलहर का कहर

एमपी में टूटी सर्दी की हदें इंदौर की रातें सबसे ठंडी

भोपाल, 13 दिसंबर. मध्यप्रदेश में इस बार सर्दी ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. इंदौर में बीते दस वर्षों की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है, जहां न्यूनतम तापमान प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी के बराबर पहुंच गया.

राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है. पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं और सक्रिय जेट स्ट्रीम के कारण पूरे प्रदेश में शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं.

प्रदेश में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है, जो सामान्य से काफी कम है. मौसम विभाग के अनुसार, इस बार सर्दी का प्रभाव सामान्य से कहीं अधिक तीव्र है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में मौसम मुख्यत: शुष्क बना रहा, हालांकि भोपाल और इंदौर जिलों में शीतलहर का स्पष्ट प्रभाव देखा गया.

पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में प्रदेश के अधिकांश संभागों में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ. ग्वालियर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा.

> मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में सक्रिय है. इसके साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडलीय स्तर पर 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रफ के रूप में विकसित हो रहा है. उत्तर-पूर्व भारत के ऊपर लगभग 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 176 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं, जिसका असर मध्यप्रदेश के भोपाल, रायसेन, राजगढ़, इंदौर और शाजापुर जिलों में साफ दिखाई दे रहा है.

धार के पूर्व राजा की वाहन पार्किंग में लगी आग

धार. धार के पूर्व राजा स्व हेमेंद्र सिंह पंवार के बंगले के परिसर में अचानक आग लगने से वहां रखे वाहन जल गए. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शानिवार सुबह तड़के करीब साढ़े 3 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पर आग लगने की सूचना मिली थी. परिसर में ही वाहनों की पार्किंग को लेकर एक टीनशेड बना हुआ हैं, जहां से अचानक आग की लपटें निकलना शुरु हो गई थी. सबसे पहले बंगले पर निवास करने वाले कर्मचारियों ने पानी की मोटरों से आग बुझाने का प्रयास किया, किंतु वाहनों के कारण आग बढ गई. सूचना मिलते ही दो फायर वाहन मौके पर पहुंचे व करीब पौन घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया.

सीएम के संदेश के बाद आंदोलन स्थगित

विशेष संवाददाता

भोपाल, 13 दिसंबर. महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री के कड़े संदेश के बाद मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ ने अपना आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा की है.

संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्पष्ट संदेश दिया है कि महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को, चाहे वे कितने ही ऊँचे पद पर क्यों न हों, बख्शा नहीं जाएगा. नायक ने आंदोलन को समर्थन देने वाले राजनीतिक नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और प्रदेशभर के पत्रकारों व मीडिया कर्मियों को विशेष धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया. यह आंदोलन 23 नवंबर 2025 को आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में भोपाल सहित अन्य स्थानों पर 18 दिनों तक चला. शुक्रवार को वल्लभ भवन के बाहर 'शंखनाद' कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था. संघ का दावा है कि आंदोलन का असर हुआ है और 12 दिसंबर 2025 को राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर वर्मा की पदोन्नति वापस लेने का अनुरोध किया है.

> उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री निवास के घेराव सहित आंदोलन के सभी कार्यक्रमों को 10 दिनों के लिए स्थगित किया गया है. यह निर्णय सामान्य वर्ग एवं ब्राह्मण समाज के नेताओं की कोर ग्रुप बैठक में लिया गया. बैठक में सकल ब्राह्मण समाज संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक वीरेंद्र शर्मा, मप्र परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजोरिया, संघ अध्यक्ष इंजीनियर सुधीर नायक, रामनारायण अवस्थी, राकेश चतुर्वेदी, पुष्पेंद्र मिश्रा, गौरीशंकर 'काका', रामबाबू शर्मा, दिनेश तिवारी, अशोक भारद्वाज सहित अनेक कर्मचारी व समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

इंदौर महानगर क्षेत्र की सीमा पर आज फैसला

इंदौर, 13 दिसंबर. प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के भविष्य को नई दिशा देने वाला अहम फैसला अब अंतिम चरण में पहुंच गया है.

इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया की सीमा और स्वरूप को लेकर नगरीय विकास विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस संबंध में बड़ा निर्णय ले सकते हैं, साथ ही शहर के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी संभावित हैं. 14 दिसंबर रविवार को इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया की औपचारिक घोषणा की जा सकती है.

> मुख्यमंत्री कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं

एमएससी नर्सिंग प्रवेश पर हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

विशेष संवाददाता

भोपाल, 13 दिसंबर. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा संचालित एमएससी नर्सिंग प्रवेश प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर गंभीर चिंता जताई.

रवि परमार लंबे समय से प्रवेश प्रक्रिया पर सवाल उठाते आ रहे हैं. पूर्व में उन्हें प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से रोका गया था, बाद में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद वे परीक्षा में शामिल हो पाए थे. अब उन्होंने एक बार फिर प्रवेश प्रक्रिया को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय ने दलील दी कि एमएससी नर्सिंग की प्रवेश प्रक्रिया मनमाने ढंग से संचालित की जा रही है. न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अधिवक्ता को 15 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए.

पमरे में स्वच्छता अभियान सख्त

08 माह में गंदगी फैलाने वालों से 24.82 लाख का जुर्माना

भोपाल, 13 दिसंबर. पश्चिम मध्य रेलवे (पमरे) अपने तीनों मंडलों—भोपाल, जबलपुर और कोटा—के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चला रहा है.

इसी कड़ी में चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से नवंबर तक गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 12,550 मामलों में कुल 24 लाख 82 हजार 940 रुपए का जुर्माना वसूला गया है. रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशनों और रेलगाड़ियों में नियमित साफ-सफाई कराई जा रही है. इसके साथ ही यात्रियों को उद्घोषणाओं के माध्यम से स्टेशन परिसर को स्वच्छ रखने, धूम्रपान न करने और कूड़ा निर्धारित स्थानों पर डालने के लिए जागरूक किया जाता है. बावजूद इसके, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत समय-समय पर जुर्माना लगाया जा रहा है. रेल प्रशासन के अनुसार, केवल नवंबर माह में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान गंदगी फैलाने के 1331 मामलों में 2 लाख 70 हजार 850 रुपए का जुर्माना वसूला गया. जुर्माने के साथ-साथ संबंधित यात्रियों को स्वच्छता के महत्व और गंदगी से होने वाले नुकसान की जानकारी देकर समझाइश भी दी गई.

> **यात्रियों से सहयोग की अपील**
>
> पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि रेलवे उनकी अपनी संपत्ति है, इसलिए स्टेशन और ट्रेन परिसर में गंदगी न फैलाएं. स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में रेल प्रशासन के प्रयासों में सहभागी बनें. रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छता को लेकर इस तरह के अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

तीखी प्रतिक्रिया प्रदेश में प्रशासनिक शिथिलता और अराजकता जैसी स्थिति बन रही है

बच्चन कानून-व्यवस्था के कथित पतन पर चिंतित

विशेष संवाददाता

भोपाल, 13 दिसंबर. मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री एवं कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

उन्होंने आरोप लगाया कि गृह विभाग के संचालन में लापरवाही के कारण प्रदेश में प्रशासनिक शिथिलता और अराजकता जैसी स्थिति बन गई है. मीडिया से बातचीत में बच्चन ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर व्यवस्था पूरी तरह विफल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि 'विकास और सेवा' जैसे नारे अब केवल प्रचार तक सीमित रह गए हैं. पिछले दो वर्षों को उन्होंने छल और कर्ज का दौर बताते हुए कहा कि प्रदेश का हर नागरिक औसतन करीब 50 हजार रुपये के आर्थिक बोझ से जूझ रहा है, जबकि महिलाओं और यहां तक कि पुलिसकर्मियों की सुरक्षा भी गंभीर रूप से कमजोर हुई है.

पूर्व गृहमंत्री ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड अभिलेख (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए हिरासत में मौतों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई और पुलिस बल में अनुशासनहीनता बढ़ने का आरोप लगाया. उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हुए हमलों की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जब सुरक्षा बल स्वयं असुरक्षित महसूस करें, तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है.

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बच्चन ने दावों और जमीनी हकीकत के बीच गहरे अंतर की ओर इशारा किया.

> उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना जैसी योजनाओं पर भारी खर्च के बावजूद प्रदेश महिलाओं के लिए असुरक्षित बना हुआ है, जहां यौन अपराध, लापता लड़कियों और मानव तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. उन्होंने उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों में बलात्कार और पॉक्सो मामलों के बड़ी संख्या में लंबित होने का भी उल्लेख किया. बच्चन ने संगठित अपराध, नशा तस्करी और साइबर धोखाधड़ी को संरक्षण मिलने का आरोप लगाया तथा भोपाल और इंदौर मेट्रो जैसी परियोजनाओं में हो रही देरी की आलोचना की. उन्होंने कथित पुलिस अत्याचारों की न्यायिक जांच, गंभीर आरोपों से घिरे पदाधिकारियों को हटाने और लापता महिलाओं व बालिकाओं की तलाश के लिए विशेष कार्यबल गठित करने की मांग की.

पेज एक का शेष

आईएएस वर्मा सेवा से होंगे बर्खास्त

में कूटरचित करने, लंबित प्रकरणों की झूठी जानकारी शासन एवं प्रशासन को देकर आईएएस अवॉर्ड प्राप्त किया.

पत्र में यह भी कहा गया है कि पुलिस अभिरक्षा में 48 घंटे से अधिक निरुद्ध रहने के कारण वर्मा को 13 जुलाई 2021 को निलंबित भी किय गया था. प्रशासकीय अनुमोदन के बाद उनके खिलाफ 11 अगस्त 2021 को आरोप पत्र भी जारी किया गया था, जिसका जवाब संतोषजनक नहीं मिला था. ऐसे में उनके खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की गई और आयुक्त उज्जैन संभाग को जांचकर्ता अधिकारी एवं उपायुक्त इंदौर संभाग को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया. विभागीय जांच अब भी प्रक्रियाधीन है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गहरी नाराजगी जाहिर की थी

जीएडी कार्मिक ने केंद्र को भेजे पत्र में कहा है कि वर्मा के खिलाफ न्यायालय में अब भी प्रकरण विचाराधीन है. ऐसे में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि वर्मा की आईएएस संवर्ग में पदोन्नति द्वारा दी गई नियुक्ति पर समुचित निर्णय लिया जाए. यहां बता दें कि लगातार विवादों के बीच ही वर्मा ने न्यायालय पर भी अमर्यादित टिप्पणी कर ली थी.

इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गहरी नाराजगी जाहिर की थी. उसके बाद ही वर्मा के खिलाफ दो दिन पहले विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई थी. अब जीएडी कार्मिक ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने के लिये केंद्र सरकार को शुक्रवार को पत्र भेज दिया है.